नई शिक्षा नीति के अधीन प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा

1543. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई शिक्षा नीति के अधीन प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन के संबंध में बनाई गई योजना सरकार को राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों की मांग के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक राज्य को उनके द्वारा मांगी गई राशि का कितने प्रतिशत सहायता दी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे शिक्षा और संस्कृति विभागों मे राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही): (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के संदर्भ में, वर्ष 1987-88 में दो नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात् आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना तथा गैर औपचारिक शिक्षा योजना (संशोधित पद्धति) प्राइमरी शिक्षा को प्रौन्नत करने के लिए आरंभ की गयीं थी। आपरेशन ब्लेकबोर्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 1987-88 में सभी एकल शिक्षा वाले स्कूलों में दूसरे शिक्षक के प्रावधान हेतु तथा केन्द्रीय प्रतिनिधियों सहित राज्य सरकारों द्वारा गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियों के अनुमोदन के आधार पर 1,13,417 प्राइमरी स्कूलों में आवश्यक अध्ययन अध्यापन उपकरण के प्रावधान हेतु 24 राज्यों तथा 3 संघ शासित क्षेत्रों को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गयी थी। कुल मिलाकर 110.61 करोड़ रुपये की राशि मुक्त की गयी थी। वर्ष 1988-89 में अब तक, राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियों द्वारा 103 66 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गयी है।

गैर औपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित तरीके से दी जाती है:—

i) गैर औपचारिक शिक्षा सह शिक्षा केन्द्र	50:50	केन्द्र राज्य की भागीदारी के आधार पर
ii) गैर औपचारिक शिक्षा कन्या केन्द्र	90:10	केन्द्र राज्य की भागीदारी के आधार पर
iii) स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र		शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता

वर्ष 1987-88 में 16 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 3803.84 लाख रु० की राशि संस्वीकृत की गयी थी तथा वर्ष 1988-89 में 2512.04 लाख रुपये की राशि अब तक संस्वीकृत की गयी है।

घाटे में चल रही रेलगाड़ियां

1544. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कुछ रेलगाड़ियों को ऐसे मार्गों पर चला रहा है कि वे लगातार घाटे में ही चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो 1986-87 में इस प्रकार घाटे में चलने वाली गाड़ियों के नाम क्या हैं और इनसे उस वर्ष मे कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इन मार्गों मे सुधार करने तथा उन्हें आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए कोई योजना लागू की है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद):

(क) जी हां।

(ख) गाड़ी-वार लाभप्रदता निर्धारित नहीं की जाती है। तथापि, वर्ष 1986-87 के दौरान अलाभप्रद शाखा लाइनों से हुई हानि 81,34.92 लाख रुपये थी।

(ग) और (घ) अलाभप्रद शाखा लाइनों की आमदनी बढ़ाने तथा कार्य संचालन व्यय यथासभव कम करने के लिए समय-समय पर निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

(i) कम लोकप्रिय गाड़ियों को चलाना बन्द करना।

(ii) अलाभप्रद स्टेशनों / हाल्टों को बन्द करना या उन्हें ठेकेदार द्वारा परिचालित हाल्टों में बदलना।

(iii) यात्री और माल गाड़ियों का मिश्रित गाड़ियों में बदलाव।

(iv) केवल एक इंजन प्रणाली लागू करना।

(v) कर्मचारी खर्च में किफायत।

(vi) खंड पर बिना टिकट यात्रा की रोकथाम।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत सरकारी बसें

1545. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली सरकारी बसों की संख्या में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1988 में प्रतिदिन दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसें सड़कों पर चलती थी और जनवरी, 1989 में उनकी संख्या कितनी थी, और

(ग) इन बसों की संख्या में कमी आने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में अप्रैल, 1988 में 4348 बसों के मुकाबले जनवरी, 1989 में 4249 बसें थी किन्तु बेड़े के बेहतर उपयोग के कारण जनवरी, 1989 में प्रतिदिन 3793 बसे सड़कों पर निकाली गई जबकि अप्रैल, 1988 मे 3619 निकाली गई थी। बेड़े की संख्या में मामूली कमी का कारण पुरानी 498 बसों की छंटनी और अब तक सिर्फ 394 बसें शामिल करना है। जिन 423 नई बसों के आर्डर दिए गए हैं, वे शीघ्र ही बेड़े में शामिल हो जाएंगी जिसके फलस्वरुप बेड़े की क्षमता में निवल वृद्धि होगी।

मध्य प्रदेश में कार्यात्मक साक्षरता

1546. **श्री अजीत जोगी: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत वर्ष 1990 तक निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान की गई है; और

(ग) मध्य प्रदेश के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वहां अब तक की उपलब्धि क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही): (क) से (ग) अद्यतन सूचना राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त की जा रही है। उपलब्धि के संबंध मे अद्यतन सूचना अभी मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त की जानी है।

पुरातत्वीय महत्व के स्थलों के संबंध में सर्वेक्षण

1547. **श्री अजीत जोगी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 9 मार्च, 1988 को राज्य सभा मे